

सेवा में,

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
Date: 12/10/2015

माननीय प्रधान मंत्री जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

आदरणीय महोदय,

मैं सुरेश प्रसाद मिश्र पुत्र श्री आदया प्रसाद मिश्र, ग्राम-बरकी, सेवापुरी, वाराणसी, UP का निवासी हूँ। मैं 12.09.2015 से एक अभियान चला रहा हूँ और इस अभियान के लिये मैं बनारस से पद यात्रा कर रहा हूँ और 10.10.2015 को दिल्ली पहुँच गया। अभियान मेरे द्वारा स्थापित "अनुराग मिश्र फाउन्डेशन" के तहत निम्न दो मुद्दों पर है।

1. Free Education Must Education
2. No Spitting on Road and Public Place

मैं आपका ध्यान पहले मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके अन्तर्गत मैंने मॉग रखी है कि हमारे देश के हर बच्चे को चाहे वह अमीर का हो या गरीब का हो और बगैर उसके जाति, धर्म में कोई भेद किये हुये, बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाये। यहाँ मैं आपको अनुरोध करूँगा कि मुफ्त शिक्षा के लिये स्तर का भी प्रतिबन्ध न हो, मतलब बच्चों को आई.आई.टी. और आई.आई.एम. स्तर तक की शिक्षा भी मुफ्त में दी जाये।

मुफ्त शिक्षा देने के फायदे :-

1. केवल वास्तविक प्रतिभा ही उपर आयेगी। खरीदी हुयी प्रतिभा नहीं।
2. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान अभी भी गाँवों में सफल नहीं है क्योंकि लोग बेटे को तो किसी तरह पढाते हैं लेकिन बेटियों को सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। मुफ्त शिक्षा करने से बेटियों की भी प्रतिभा सामने आयेगी।

शेष पेज 2 पर.....

3. वर्तमान परिस्थितियों में माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिये अपनी हैसियत से ज्यादा पैसों का इन्तजाम करने के लिये गलत तरीका भी अपना रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अगर शिक्षा मुफ्त कर दी जाये तो काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।
4. पिछले कुछ चर्चित असामाजिक कार्यों को देखा जाये तो उनको करने वालों में एक समानता पायी जायेगी और यह समानता उनको अशिक्षित होना है, और ये लोग अशिक्षित इसलिये रह गये कि इनके माता-पिता इनको शिक्षित करने की स्थिति में नहीं थे। अगर शिक्षा मुफ्त कर दी जाये तो ज्यादातर असामाजिक अपराधों पर अंकुश अपने आप लग जायेगा।

हमारे देश का एक ज्वलंत और बहुत ही भयानक बिमारी है जिसका जिक्र आपसे मुलाकात के बाद ही कर सकता हूँ, को भी इस मुफ्त शिक्षा योजना से समाप्त किया जा सकता है।

योजना के लिये पैसों का इन्तजाम निम्न तरीके से किया जा सकता है:-
हमारे देश की ज्यादातर जनता का विचार है कि सरकार की जितनी भी चैरिटी योजनायें हैं जैसे मिड डे मील, मनरेगा, किसी भी प्रकार की सब्सीडी ये सभी बन्द करके सभी पैसों को मुफ्त शिक्षा योजना में लगाया जाये।

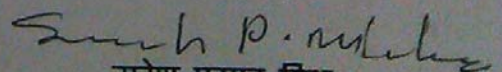
महोदय हमारे देश की शिक्षा नीति बदल कर केवल एक ही शिक्षा बोर्ड देश में रखा जाये। अलग-अलग राज्यों के बोर्डो को खत्म कर दिया जाये और केवल केन्द्र ही सारे स्कूलों और कालेजों को नियंत्रित करे।

महोदय इस नीति के तहत देश में कोई भी स्कूल और कॉलेज निजी नहीं होंगे, सभी संस्थाओं का राष्ट्रियकरण कर दिया जाये।

महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा समय मेरे लिये भी दीजिये तो कुछ बातें जो मैं अपने पद यात्रा के दौरान जनता के बीच प्राप्त उसको आपके साथ बाँटना चाहता हूँ।

धन्यवाद,

आपका प्रार्थी,


सुरेश प्रसाद मिश्र